Future of capitalism
पूंजीवाद का भविष्य

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था अपने विशुद्ध रूप में आज कहीं नहीं पाई जाती अर्थात् इसकी पाँच आधारभूत विशेषताएँ—निजी सम्पत्ति, स्वतन्त्र व्यवसाय, उपभोक्ता की प्रभुता, लाभ, उद्देश्य और स्वतन्त्र मूल्य-संयन्त्र—पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं होती। प्रायः हर पूँजीवादी देश में ये पाँचों मुख्य विशेषताएँ किसी न किसी रूप में प्रतिबन्धित हैं। वास्तव में आज का पूँजीवाद 19वीं शताब्दी के पूँजीवाद से बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है जिसमें समयानुकूल पर्याप्त सुधार किए जा रहे हैं। पूँजीवाद की यही लोचशीलता उसके जीवित रहने का मुख्य कारण है और इसी के बल पर भविष्य में पूँजीवाद बना रहेगा।

पूँजीवाद का अपने विशुद्ध रूप में अस्तित्व नहीं है, उसका प्रचलित रूप बहुत कुछ परिवर्तित-परिष्कृत हो चुका है। ये परिवर्तन कुछ दृष्टियों से इतने व्यापक हैं कि यदि पूँजीवाद के गढ़ अमेरिका को नए ढंग से पूँजीवाद का प्रतीक कह दिया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अधिकाँश पूँजीवादी देशों में—

(1) पूँजीवादी बाजार की अपूर्णताएँ (Market Imperfections) उत्पन्न हो गई हैं जिनमें से कुछ के लिए निजी क्षेत्र उत्तरदायी हैं तो कुछ के लिए सरकार। पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में अनेक क्रेताओं की कीमत पर किसी एक क्रेता अथवा विक्रेता का प्रभाव नहीं पड़ता। पर इस सम्बन्ध में बाजार-अपूर्णताएँ दोनों पक्षों की ओर से उत्पन्न हो गई हैं। क्रेता पक्ष की ओर से एक क्रेता (Monopsony), दो क्रेता (Duopsony), तथा कुछ क्रेता (Oligospony) की

Scanned by CamScanner

स्थिति पायी जाने लगी है। इसी प्रकार विक्रेता पक्ष की ओर से एक विक्रेता अथवा एकाधिकारी (Monopoly), दो विक्रेता (Duopoly) तथा कुछ विक्रेता (Oligopoly) की दशाएँ उत्पन्न हो गई हैं। इन स्थितियों में बाजार की अपूर्णताएँ क्रियाशील हैं। उदाहरणार्थ, एकाधिकार के अन्तर्गत, पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा की तुलना में, उत्पादन कम और लागत अधिक होती है। एकाधिकारी का मुनाफा भी उत्पादन की एक दी हुई मात्रा के लिए अपेक्षाकृत काफी अधिक अथवा बढ़ा-चढ़ा होता है।

(2) कम्पनी अथवा निगम के आधार पर संगठन विकसित हुए है जिनसे स्वामित्व और नियन्त्रण के बीच खाई उत्पन्न हो गई है। हिस्सेदार कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं जबकि वेतनभोगी मैनेजर प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(3) श्रमिकों के संगठन विकसित हो गए हैं, अतः उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ चुकी है और वे प्रतिस्पर्द्धात्मक मजदूरी से अधिक मजदूरी प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। इस प्रकार मजदूर संघों की ओर से भी बाजार-अपूर्णता को बल मिला है।

(4) आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और उन पर सरकार का पर्याप्त अंकुश रहता है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ ही निजी उद्योगों का नियमन किया है। स्वतन्त्र बाजार प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है और उसे सरकार द्वारा नियमित किया जाने लगा है।

(5) आर्थिक उतार-चढ़ाव और वित्तीय असमानताओं आदि को ठीक करने के लिए सरकार बजट सम्बन्धी तथा मौद्रिक उपाय अपनाकर आगे बढ़ रही है। वर्तमान कर प्रणाली, मृत्यु-कर आदि द्वारा वित्तीय असमानताओं को दूर किया जाता है। मन्दी के समय कर घटाकर व्यय में कटौती की जाती है तथा साख नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के फलस्वरूप पूँजीवाद अपने विशुद्ध रूप में नहीं रहा है।

(6) लाभ-हिस्सा योजना, बोनस योजना, प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी आदि व्यवस्थाएँ पूँजीवादी देशों में पनप रही हैं।

इन सभी बातों से स्पष्ट है कि समय के साथ पूँजीवाद व्यवस्था में बहुत संशोधन किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन पूँजीवाद के विशुद्ध सिद्धान्त से मेल नहीं खाते। नए किस्म का पूँजीवाद पुराने किस्म के पूँजीवाद से पर्याप्त भिन्न है। पूँजीवाद का भविष्य भी उसके संशोधन रूप और लोचपूर्ण प्रभाव में ही निहित है।

पूँजीवाद का कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तन
(Transformation of Capitalism to a Welfare State)

19वीं शताब्दी में पूँजीवादी आर्थिक प्रणालियों ने बहुत अधिक प्रगति की

Scanned by CamScanner

इस शताब्दी में उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा भौतिक दृष्टि से सम्पन्नता बढ़ी, किन्तु बीसवीं शताब्दी में यह माना जाने लगा कि पूँजीवाद युद्ध द्वारा विनाश को बढ़ाता है, महान् मन्दी की तरह भयंकर उच्चावचनों को जन्म देता है, सम्पत्ति और धन की असमानताएँ बढ़ाता है, उपनिवेशवाद तथा सामाजिक अशान्ति को जन्म देता है। ऐसी मान्यताओं के विकसित होने के कारण बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से 1939 ई. तक का समय पूँजीवाद के विकास की दृष्टि से बड़ा विवादास्पद रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के समय को भी पूँजीवाद के विकास की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। समाजवादी विचारकों के अनुसार श्रमिक क्रान्ति द्वारा पूँजीवाद समाप्त हो जाएगा जबकि दूसरे विचारक क्रान्ति में विश्वास नहीं रखते। शुम्पीटर के अनुसार पूँजीवादी फर्म की ताकतों में कमी तथा उद्योगों में घाटे के कारण द्वारा पूँजीवाद धीरे-धीरे समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में पूँजीवादी आर्थिक प्रणालियों ने न केवल स्थिरता प्राप्त की बल्कि उत्पादन क्षमता में भी विलक्षण वृद्धि हुई। पश्चिमी जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, फ्राँस तथा जापान के विकास की दर में वृद्धि इस तथ्य को स्पष्ट करती है अतः यह मानना कि पूँजीवाद श्रम-क्रान्तियों या स्वतः समाजवाद में परिवर्तित हो जाएगा शंकास्पद है।

राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि तथा स्थिर एवं सन्तुलित आर्थिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान् मन्दी के बाद एक सुदृढ़ सरकार की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी तथा पूँजीवाद का स्वरूप कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित होना प्रारम्भ हुआ। इस परिवर्तन के लिए निम्न घटकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(1) प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रबन्धकीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। पहले पूँजी का मालिक स्वयं मैनेजर हुआ करता था इसलिए पूँजी तथा प्रबन्ध में एकीकरण विद्यमान था। इस व्यवस्था में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, बड़े औद्योगिक तथा वित्तीय निगमों की व्यवस्था का भार एक नए वेतनभोगी वर्ग मैनेजर के हाथों में आ गया जिनकी स्वयं की पूँजी बहुत कम या नहीं के बराबर होती थी। इस परिवर्तन से यद्यपि औद्योगिक सम्बन्ध तथा आर्थिक संगठन की कुशलता में वृद्धि हुई किन्तु पूँजीपतियों के महत्त्व में कमी प्रारम्भ हो गई।

(2) पूँजी संचय की प्रकृति में परिवर्तन—औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विनियोग के लिए पूँजी मुख्य रूप से निजी बचतों द्वारा प्राप्त हुआ करती थी। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तकनीकी विकास के लिए पूँजी एकत्रित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई। अंशधारियों के लाभांश का एक भाग इस उद्देश्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था और उसके बाद भी यदि पूँजी की आवश्यकता होती तो वित्तीय संस्थाओं से पूँजी उधार ले ली जाती थी। पूँजी संचय की नई

Scanned by CamScanner

विधि ने प्रबन्धकों की स्थिति को अधिक सुदृढ़ बना दिया तथा तकनीकी प्रगति को सम्भव बनाया।

(3) **पूँजी एवं श्रम में एकीकरण**—आधुनिक पूँजीवाद में पूँजी और श्रम में एकीकरण प्रारम्भ हुआ, इसके परिणामस्वरूप श्रमिक पूँजी के स्वामी हो गए। अतः पूँजीपति और श्रमिकों में भेद करना कठिन हो गया। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप सम्पत्ति तथा आय के वितरण में परिवर्तन हुआ तथा केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति कम हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पूँजीवादी राष्ट्रों में सम्पत्ति का स्वामी होना प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है यदि यह सम्पत्ति स्वय के श्रम तथा प्रयासों से अर्जित की गई हो। यही कारण है कि अमेरिका में कार्य करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिक रूप से अनिवार्य है अतः प्रत्येक पूँजीपति एवं श्रमिक सम्पत्ति तथा आय अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। पूँजी एवं श्रम के एकीकरण, आय वितरण में परिवर्तन तथा कार्य के प्रति लगाव ने पूँजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन को जन्म दिया।

(4) **पूँजीवाद के स्थान पर 'उपभोक्तावाद' का प्रारम्भ**—कीन्स के प्रभावपूर्ण माँग के सिद्धान्त ने भी पूँजीवाद के ढाँचे में परिवर्तन को जन्म दिया। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण माँग में कमी मन्दी को तथा प्रभावपूर्ण माँग का आधिक्यता मुद्रा प्रसार को जन्म देती है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर पूँजीवादी राष्ट्रों में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कीमतों में कमी करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई इसलिए इस काल को 'उपभोक्तावाद' भी कहा जाने लगा। आधुनिक पूँजीवाद में लाभ कमाने के लिए कम उत्पादन और अधिक कीमतों के स्थान पर अधिक उत्पादन और कीमतों तथा अधिक दक्षता के लिए ऊँची मजदूरी की नीति को आधार माना जाने लगा है तथा माँग में वृद्धि के लिए विज्ञापन, गुण एवं बिक्री संवर्द्धन की नीतियों के प्रयोग में वृद्धि प्रारम्भ हुई है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की इस नीति से पूँजी श्रम एवं उपभोक्ताओं में संघर्ष की स्थिति में महत्त्वपर्ण गिरावट आई और पूँजीवाद का कल्याणकारी स्वरूप प्रारम्भ हुआ।

(5) **पूँजीवादी प्रणालियों में नियोजन के प्रयोग में वृद्धि**—पूँजीवादी आर्थिक प्रणालियाँ स्वतन्त्र उद्यम वाली प्रणालियाँ थी किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन राष्ट्रों में भी नियोजन का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। यद्यपि पूँजीवादी राष्ट्रों में समाजवादी या साम्यवादी देशों की तरह केन्द्रीय नियोजन नहीं पाया जाता किन्तु इन राष्ट्रों में जिस तरह के नियोजन का प्रयोग प्रारम्भ हुआ है उसे 'प्रयोगात्मक नियोजन' (Tentative Planning) या 'उदार नियोजन' (Liberal Planning) कहा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशेष संगठन है जो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन द्वारा पूर्वानुमान लगाते हैं तथा आर्थिक क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में सरकार तथा व्यापारियों को सचेत कर देते हैं तथा उससे छुटकारा पाने के उपाय भी सुझाते हैं। यहाँ तक कि सरकार कानूनी रूप से भी आने वाले संकट से छुटकारा पाने का प्रयास कर सकती है। इस प्रकार नियोजन के

Scanned by CamScanner

प्रयोग में वृद्धि से यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी प्रणालियां स्वतन्त्र उद्यम वाली प्रणालियों से नियन्त्रित प्रणालियों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं।

(6) राजनीतिक-आर्थिक साम्यावस्था—युद्धोत्तरकालीन पूंजीवाद का मुख्य लक्षण राजनीतिक आर्थिक साम्यावस्था का स्थापित होना है। पूंजीवादी राष्ट्रों में सरकार, व्यवसाय और संगठित श्रम में परस्पर समन्वय तथा सन्तुलन की स्थापना ने इसके स्वरूप को कल्याणकारी बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक पूंजीवाद समय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढाल रहा है तथा वर्तमान में इसका स्वरूप कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है।

हम समाजवादियों के इस तर्क का कि पूंजीवाद का अन्त किया जाय तो खण्डन कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि 'पूंजीवाद में सुधार सम्भव है, इसका अन्त करने की आवश्यकता नहीं है।'

Scanned by CamScanner